



IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Week-5&6 Compilation



DELHI

BANGALORE

5B, Pusa Road, Karol
Bagh, New Delhi - 110005.
Landmark: Just 50m from
Karol Bagh Metro Station,
GATE No. 8 (Next to
Croma Store)
Ph: 0114167500

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar
Service Road, Vijaynagar, Bangalore
560040. PH: 09035077800 /
7353277800



support@iasbaba.com



www.iasbaba.com

Q.1) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है

- वित्त मंत्री
- आरबीआई गवर्नर
- वित्त सचिव
- प्रधान मंत्री

Q.1) Solution (a)

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- एफएसडीसी वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले क्षेत्रक नियामकों (sectoral regulators) का सर्वोच्च निकाय है।
- सभी वित्तीय क्षेत्रक नियामक प्राधिकरणों जैसे कि RBI, SEBI, IRDA, PFRDA आदि के प्रमुख, FSDC के सदस्य होते हैं।
- राज्य मंत्री, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, परिषद में नए जोड़े गए हैं।

Q.2) भारत के कर संग्रह के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।
- निगम कर का हिस्सा वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से अधिक है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.2) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
व्यक्तिगत आयकर का हिस्सा पिछले पांच वर्षों से लगातार बढ़ा है।	निगम कर की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी से कम है

Q.3) छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं के माध्यम से संचित धन कहाँ रखा जाता है

- भारतीय समेकित कोष
- भारतीय सार्वजनिक खाते
- भारतीय आकस्मिकता निधि
- संबंधित राज्य के समेकित निधि

Q.3) Solution (b)

- भारतीय सार्वजनिक खाता संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित किया गया है।

- भारत के समेकित कोष में शामिल धन के अलावा प्राप्त सभी सार्वजनिक धन भारत के सार्वजनिक खाते में आयोजित किए जाते हैं।
- इस खाते में मुख्य रूप से छोटी बचत योजनाओं, भविष्य निधि योजनाओं आदि के माध्यम से धन संचित किया जाता है।
- सरकार केवल इन फंडों की संरक्षक होती है। इसे या तो परिपक्वता तिथि पर या जब भी लोगों द्वारा दावा किया जाता है, चुकाना पड़ता है।

Q.4) निम्नलिखित में से किसे सरकार के गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (Non-Tax Revenue receipts) के रूप में माना जाता है

1. स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
2. मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन से लाभ।
3. निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से लाभांश।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.4) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होती हैं।	मुद्रा, सिक्का और टकसाल अन्य गैर-कर प्राप्तियों की वित्तीय सेवाओं के तहत आते हैं।	गैर-कर राजस्व - लाभांश निजी उद्यमों में सरकारों द्वारा रखे गए शेयरों से आय है।

गैर-कर राजस्व प्राप्तियां

- ब्याज प्राप्तियां
- लाभांश और लाभ
- मुद्रा, सिक्का, टकसाल
- सामाजिक सेवा
- सहायता अंशदान में अनुदान
- आर्थिक सेवाएँ

पूंजीगत प्राप्तियां

- स्थायी संपत्ति के निपटान के कारण प्राप्तियां
- दूसरों को दिए गए ऋणों की वसूली
- सरकार द्वारा लिया गया उधार

Q.5) स्थायी संपत्ति बनाने तथा समय-समय पर आय अर्जित करने वाले व्यय को कहा जाता है

- a) राजस्व व्यय

- b) परिसंपत्ति व्यय
- c) पूंजीगत व्यय
- d) प्राथमिक व्यय

Q.5) Solution (c)

- पूंजीगत व्यय, वे व्यय हैं
 - जो स्थायी संपत्ति बनाते हैं और समय-समय पर आय देते हैं।
 - राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में दिए जाते हैं।
- यह दो तरफा भुगतान होते हैं। इसका मतलब है कि व्यय किए गए धन को आवधिक आय और / या बनाई गई संपत्ति के निपटान के माध्यम से वापस प्राप्त किया जा सकता है।

Q.6) राजकोषीय घाटे (Fiscal deficit) को संदर्भित करता है

- a) उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
- b) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
- c) ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.6) Solution (a)

राजकोषीय घाटा	उधार को छोड़कर, सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अंतर।
प्राथमिक घाटा	ब्याज आय और भुगतान को छोड़कर सरकार की कुल आय और व्यय के बीच अंतर।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा एक आर्थिक क्रिया है, जहां सरकार का कुल व्यय उत्पन्न राजस्व से अधिक होती है।
- राजकोषीय घाटा सरकार को सभी स्रोतों से कुल उधार आवश्यकताओं के बारे में संकेत देता है।

Q.7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है।
2. कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.7) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कर प्लवनशीलता (Tax Buoyancy) जीडीपी में परिवर्तन के लिए कर राजस्व वृद्धि की जवाबदेही को संदर्भित करता है। कर प्लवनशीलता = कर राजस्व में परिवर्तन / सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात में परिवर्तन का अनुपात।	कर लोचशीलता (Tax elasticity) में कर दर में परिवर्तन के प्रतिउत्तर में कर राजस्व में परिवर्तन को संदर्भित करता है।

Q.8) वस्तु एवं सेवा कर (GST) निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है?

1. एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं।
2. एक नए भवन के निर्माण में एक बिल्डर द्वारा सेवाएं।
3. दूध बूथों और किराने की दुकानों में उपलब्ध स्वादिष्ट दूध (flavoured milk)।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (c)

विकल्प 1	विकल्प 2	विकल्प 3
असत्य	सत्य	सत्य
एक कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के संबंध में सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं। हालांकि, कर्मचारी कमाए गए वेतन पर आयकर का भुगतान करेगा।	एक नए भवन का निर्माण जीएसटी (कार्य अनुबंध होने के नाते) के अधीन है।	गैर-स्वाद वाले दूध और दूध पाउडर को जीएसटी से छूट दी गई है लेकिन स्वादिष्ट दूध पर 12% स्लैब के तहत जीएसटी कर लगाया जाता है।

Prelims 2020 Exclusive :Current Affairs Classes

Beat the Heat of Current Affairs Prelims 2020 in 12 Uber Cool Sessions by Tauseef Ahmad (One of the Founders of IASbaba)

MOST PROBABLE PRELIMS
CURRENT AFFAIRS TOPICS
FROM PAST 1.5 YEARS WILL
BE COVERED IN 12 SESSIONS



CRISP AND ORGANISED
NOTES/CONTENT TO MAKE
YOUR REVISION EASIER



Starts 15th April

Q.9) विनिवेश (Disinvestment) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती है।
2. निजी क्षेत्र को स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण रणनीतिक विनिवेश के रूप में जाना जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (c)

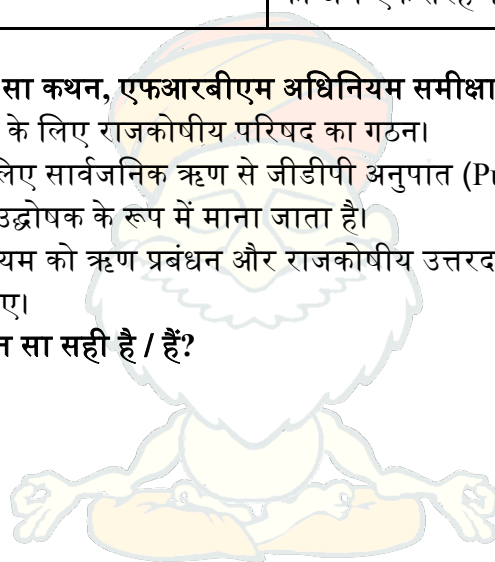
कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
कार्यवाही राष्ट्रीय निवेश कोष में अलग से की जाती है। अर्जित निधि का उपयोग चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किया जाता है। यह कोष भारत के समेकित कोष से बाहर रखा गया है।	रणनीतिक विनिवेश किसी अन्य इकाई (ज्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का हस्तांतरण है। साधारण विनिवेश के विपरीत, रणनीतिक विनिवेश का अर्थ एक तरह का निजीकरण है।

Q.10) निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एफआरबीएम अधिनियम समीक्षा समिति की सिफारिशें हैं?

- सरकार को सलाह देने के लिए राजकोषीय परिषद का गठन।
- राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात (Public debt to GDP ratio) को एक मध्यम अवधि के उद्घोषक के रूप में माना जाता है।
- एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- केवल 1 और 2
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 3
- उपरोक्त सभी



Q.10) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
‘राजकोषीय परिषद’ की स्थापना, एक स्वतंत्र निकाय, जो किसी भी वर्ष के लिए सरकार की राजकोषीय घोषणाओं की निगरानी का काम करेगा।	राजकोषीय नीति के लिए सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात को एक मध्यम अवधि के एंकर के रूप में माना जाता है। केंद्र सरकार के लिए 38.7% का ऋण-से-जीडीपी अनुपात है, यह राज्य सरकारों के लिए 20% है	एफआरबीएम अधिनियम को ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम से प्रतिस्थापित किया जाए।

Q.11) अग्रिम मूल्य समझौता (Advance pricing Agreement) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है।
2. इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह एक करदाता और कर प्राधिकरण के बीच एक संभावित समझौता है। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कई संस्थाओं के साथ एक एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं।	इसका उपयोग भविष्य के विवादों से बचने के लिए करदाताओं के अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पद्धति और देनदारियों के निर्धारण के लिए किया जाता है। यह बेहतर अनुपालन के साथ-साथ बेहतर कर निगरानी दोनों में मदद करता है।

Q.12) निम्नलिखित में से कौन 15 वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तें (terms of reference) हैं

1. राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना।
2. बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन।
3. जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.12) Solution (d)

15 वां वित्त आयोग - संदर्भ की शर्तें (Terms of reference)

- जीएसटी के विस्तार के लिए किए गए प्रयास
- जनसंख्या नियंत्रण के उपाय
- बिजली क्षेत्र में हानि का उन्मूलन
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाना
- स्थानीय निकायों को अनुदान
- स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रगति
- लोकलुभावन उपायों पर नियंत्रण।

Q.13) वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है।
2. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
एफआईआई राज्यों को अंतिम-छोर तक बैंकिंग सेवा उपलब्धता पर उनके प्रदर्शन पर आधारित होता है। 3 आयाम - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता	यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।

Q.14) आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) परियोजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह परियोजना बीईपीएस से निपटने के लिए ओईसीडी का एक परिणाम है।
2. भारत ने कर चोरी की जाँच पर ओईसीडी की परियोजना को लागू करने के लिए बहुपक्षीय कन्वेंशन की पुष्टि की है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.14) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण (BEPS) से निपटने के लिए यह परियोजना आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) / G20 का एक परिणाम है।	भारत इस परियोजना का संस्थापक सदस्य था। भारत ने 2016 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।

Q.15) निम्न में से किसे पिगोवियन कर (Pigovian tax) माना जाता है

- a) अमीरों पर संपत्ति कर
- b) कोयले पर स्वच्छ ऊर्जा उपकरण
- c) विलासिता की वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.15) Solution (b)**पिगोवियन कर (Pigovian tax)**

- एक पिगोवियन (Pigouvian) कर एक ऐसा कर है, जिसका मूल्यांकन निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के खिलाफ उन गतिविधियों में संलग्न होने के लिए किया जाता है, जो समाज के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा करते हैं।
- इनमें पर्यावरण प्रदूषण, तंबाकू उत्पादों की बिक्री से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर दबाव तथा बाहरी, नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अन्य दुष्प्रभाव शामिल होते हैं।
- पिगोवियन कर का अर्थ उन गतिविधियों को हतोत्साहित करना है जो उत्पादन की लागत को तीसरे पक्ष और समाज पर एक संपूर्ण के रूप में लगाती हैं।

Q.16) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तहत एक समिति है।
2. बीसीबीएस द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.16) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
यह बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के तहत एक समिति है। बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) बैंकों के विवेकपूर्ण नियमन के लिए प्राथमिक वैश्विक मानक-सेटर है	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) द्वारा विकसित बेसल III उपायों का उद्देश्य बैंकों के विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।

Q.17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लोकसभा में बिना किसी चर्चा के लेखानुदान (Vote on account) पारित किया जाता है
2. पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित होता है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित होता है
3. चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (d)

लेखानुदान अनुदान देने तथा विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक सरकार को कार्यप्रणाली संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए अग्रिम रूप में एक अनुदान है। यह सरकार को कम समय के लिए या एक पूर्ण-बजट पारित होने तक खर्च करने में सक्षम बनाता है। एक कन्वेंशन के रूप में, एक लेखानुदान को औपचारिक मामला माना जाता है और बिना चर्चा के लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है।

पूर्ण बजट और लेखानुदान के बीच अंतर

पूर्ण बजट, व्यय और राजस्व पक्ष दोनों से संबंधित है, लेकिन लेखानुदान केवल सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है।

लेखानुदान आम तौर पर दो महीने के लिए वैध होता है लेकिन एक पूर्ण बजट 12 महीने (एक वित्तीय वर्ष) के लिए मान्य होता है।

एक लेखानुदान प्रत्यक्ष करों में बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें एक वित्त बिल के माध्यम से पारित करने की आवश्यकता होती है। नियमित बजट के तहत, नए कर लगाए जा सकते हैं और पुराने समाप्त किये जा सकते हैं।

सभी व्यावहारिक अर्थों में एक अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट होता है लेकिन सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष के दौरान - अर्थात् चुनाव से ठीक पहले बनाया गया होता है। एक अंतरिम बजट खातों का एक पूरा सेट है, जिसमें व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। लेकिन इसमें बड़े नीतिगत प्रस्ताव नहीं हो सकते हैं।

चुनावी वर्ष में सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है।

Q.18) आभासी मुद्राओं (Virtual Currencies) पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी

- उदय कोटक समिति
- नंदन नीलेकणी समिति
- नचिकेत मोर समिति
- सुभाष चंद्र गर्ग

Q.18) Solution (d)

- आभासी मुद्राओं पर अंतर-मंत्रालयी समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने की थी।
- मुख्य सिफारिशें**
 - निजी क्रिप्टो-मुद्राओं के सभी रूपों पर प्रतिबंध।
 - देश में एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत को देखना।
 - डेटा संरक्षण विधेयक में प्रस्तावित डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।
- केंद्र द्वारा गठित समिति ने एक मसौदा विधेयक-क्रिप्टो-मुद्रा का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 के विनियमन 'का भी प्रस्ताव किया है।

Q.19) भारत सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) की स्थापना के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। NDIAC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. NDIAC एक पेशेवर रूप से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।
2. NDIAC अधिनियम NDIAC को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
NDIAC एक पेशेवर, लागत प्रभावी और समय पर ढंग से मध्यस्थता और सुलह के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा।	NDIAC अधिनियम, 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह NDIAC को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करता है।

- NDIAC अधिनियम ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान (ICADR) को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया है।
- NDIAC मध्यस्थता का एक स्थायी पैनल बनाए रखेगा जो चैंबर ऑफ़ आर्बिट्रेशन की स्थापना करेगा।
- NDIAC मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने तथा वैकल्पिक विवाद समाधान के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक मध्यस्थता अकादमी भी स्थापित कर सकता है।

Q.20) मानक कटौती (Standard Deduction) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह वेतनभोगी व्यक्तियों को उन खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति देता है, जो उसके या उसके रोजगार के संबंध में खर्च होंगे
2. इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है
3. इसे पहली बार बजट 2019 में प्रस्तुत किया गया था

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
अपने बजट 2018 के भाषण में, वित्त मंत्री ने कर्मचारियों को वेतन	इस कटौती का दावा करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं	वर्ष 1974 में आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत वेतनभोगी

आय से 40,000 रुपये की मानक कटौती प्रदान करने (पुनः प्रदान करने) का प्रस्ताव दिया था। मानक कटौती से वेतनभोगी व्यक्तियों को अपने या अपने रोजगार के संबंध में होने वाले खर्चों के लिए आय से एक फ्लैट कटौती का दावा करने की अनुमति मिलती है।	होती है।	करदाताओं के लिए मानक कटौती की शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में आकलन वर्ष 2006-07 से इसे समाप्त कर दिया गया। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा मानक कटौती को वापस लेने का यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि बुनियादी छूट सीमा और धारा 80C की कटौती में बराबर वृद्धि हुई है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कर योग्य वेतन मानक कटौती के कारण नीचे आ जाएगा।
--	----------	--

Q.21) पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFDA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह PFDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
2. यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का प्रबंधन और नियमन करता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
यह PFDA अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।	PFDA भारत का एक पेंशन नियामक है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का प्रबंधन और नियमन करता है तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को भी प्रशासित करता है।

Q.22) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. यह ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा।
2. इसमें सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी।
3. इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किसी भी कंपनी की जांच करने की शक्ति होगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3

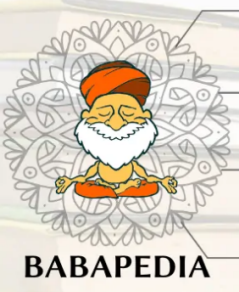
d) उपरोक्त सभी

Q.22) Solution (a)

- ऑडिट फर्में हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले जैसे विभिन्न कॉर्पोरेट घोटालों में कथित चूक के लिए जांच के दायरे में हैं।
- इस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- एनएफआरए का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा लाया गया प्रमुख परिवर्तनों में से एक था।
- NFRA ऑडिटिंग पेशे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करेगा।

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
NFRA ऑडिटिंग पेशे की देखरेख करने वाला एक स्वतंत्र नियामक होगा। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से सभी अधिकार लेगा।	इसमें सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी।	इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, 1949 के तहत पंजीकृत ऑडिटर्स की जांच करने की शक्ति होगी

**ONE STOP DESTINATION FOR ALL YOUR
CURRENT AFFAIRS NEEDS**



BABAPEDIA

- **UPDATED ON A DAILY BASIS**
- **PRECISE AND CRISP CURRENT AFFAIRS NOTES**
- **NO NEED TO MAKE NOTES FOR CURRENT AFFAIRS**
- **ONE OF ITS KIND COMPENDIUM OF CURRENT AFFAIRS**

SUBSCRIBE NOW

-  The most organized Platform for Current Affairs Preparation.
-  Highest Hit Ratio in Prelims (Current Affairs)
-  Highly Recommended by UPSC Toppers - Rank 4, 6, 9, 14, etc.

Q.23) निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें

	समिति	अध्यक्ष
1	म्युनिसिपल बांड विकास समिति	सुजीत प्रसाद
2	प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति	जयंत आर वर्मा
3	द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति	टी वी मोहनदास पई

ऊपर दी गई कौन सी जोड़ी गलत तरीके से मेल खाती है?

- केवल 1 और 2
- केवल 3
- केवल 2 और 3

d) 1, 2 और 3

Q.23) Solution (c)

युग्म 1	युग्म 2	युग्म 3
सत्य	असत्य	असत्य
इसकी अध्यक्षता सुजीत प्रसाद कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: a. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों के प्राथमिक और द्वितीयक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। b. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। c. प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना। d. म्युनिसिपल ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए जारीकर्ताओं (यानी नगर पालिकाओं) को सुविधाजनक बनाने के उपायों पर सेबी की सिफारिश करना।	इसका नेतृत्व टी वी मोहनदास पई कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. भारत में प्राथमिक बाजार के विनियमन और विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। 2. प्राथमिक बाजार में प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण और पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए जरूरी मामलों पर सेबी को सलाह देना। 3. प्राथमिक बाजार में निवेशक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिचौलियों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सेबी को सलाह देना।	इसकी अध्यक्षता जयंत आर वर्मा कर रहे हैं समिति के लिए संदर्भ की शर्तें: 1. माध्यमिक बाजार में विकास की समीक्षा करना; 2. आसन्न परिवर्तनों को देखते हुए बाजार संरचना में परिवर्तन और सुधार के उपायों की सिफारिश करना; 3. बाजार की सुरक्षा, दक्षता, पारदर्शिता और अखंडता में सुधार के उपायों की सिफारिश करना; 4. लेनदेन लागत को कम करने के उपाय सुझाना; 5. यदि जोखिम प्रबंधन / मार्जिन प्रणाली में आवश्यक हो तो परिवर्तन की सिफारिश करना; 6. द्वितीयक बाजार में नियामक ढांचे में आवश्यकता होने पर परिवर्तन की सिफारिश करना;

Q.24) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. योजना का कार्यान्वयन निकाय भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) होगा
2. इसका उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है
3. इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 3

d) उपरोक्त सभी

Q.24) Solution (d)

वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को आरंभ करने के लिए अपनी वास्तविक स्वीकृति दी है।

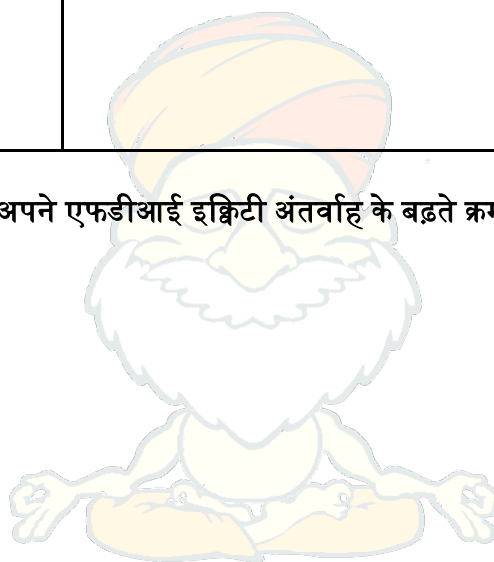
कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना का कार्यान्वयन निकाय होगा।	इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके बुढ़ापे के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।	इस योजना के तहत, प्रति वर्ष 8% के लाभ की गारंटी दर के साथ एक सुनिश्चित पेंशन दस वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, नॉमिनी के पास मासिक / त्रैमासिक / अर्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प होगा।

Q.25) 2018-19 में भारत को अपने एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित देशों को व्यवस्थित करें

1. अमेरीका
2. मॉरीशस
3. सिंगापुर
4. नीदरलैंड

सही कूट चुनें

- a) 1-4-2-3
- b) 4-1-3-2
- c) 3-2-4-1
- d) 4-1-2-3



Q.25) Solution (a)

भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) इक्विटी अंतर्वाह 2018-19 में छह वर्ष में पहली बार टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल और पावर में विदेशी फंडों की अधिक गिरावट के साथ नीचे गया है।

मंगलवार को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 1% घटकर 44.4 बिलियन डॉलर 2018-19 हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 44.8 बिलियन डॉलर था।

एफडीआई प्रवाह दूरसंचार में 56% गिरकर \$ 2.7 बिलियन तथा 74% फार्मास्यूटिकल्स में गिरकर 266 मिलियन डॉलर हो गया है।

इसके अलावा, सिंगापुर ने मॉरीशस को एफडीआई के साथ विदेशी निवेश के शीर्ष स्रोत के रूप में प्रतिस्थापित किया, जो मॉरीशस से \$ 8.1 बिलियन की तुलना में \$ 16.2 बिलियन के साथ वर्ष के दौरान मॉरीशस से दोगुना है।

नीदरलैंड (3,870 मिलियन डॉलर), इसके बाद यूएसए (3,139 मिलियन डॉलर) और जापान पांचवें (2,965 मिलियन डॉलर) स्थान पर रहा

Q.26) निम्नलिखित में से किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 प्रकाशित की है?

- अंकटाड (UNCTAD)
- विश्व आर्थिक मंच
- विश्व बैंक
- UNDESA

Q.26) Solution (a)

विश्व निवेश रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों की निगरानी तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश नीति के विकास का दस्तावेजीकरण करके नीति निर्माताओं का समर्थन करती है।

इस वर्ष की रिपोर्ट का नीति अध्याय अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों के सुधार और नए उपायों का सर्वेक्षण करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण करता है।

समावेशी सतत विकास एक वैश्विक नीति वातावरण पर निर्भर करता है, जो सीमा पार निवेश के लिए अनुकूल होता है।

विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 वैश्विक एसईजेड परिदृश्य का अवलोकन प्रदान करता है तथा सतत विकास अनिवार्यता, नई औद्योगिक क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन के बदलते पैटर्न द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत चुनौतियों का प्रतिउत्तर देने के बारे में सलाह देता है।

Q.27) भारतीय संदर्भ में, छाया बैंकिंग (Shadow Banking) के घटकों में शामिल हैं

- मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds)
- क्रेडिट निवेश कोष (Credit investment Fund)
- हेज फंड (Hedge Funds)
- एनबीएफसी

सही कूट चुनें

- केवल 1, 2 और 3
- केवल 2, 3 और 4
- केवल 1, 3, और 4
- उपरोक्त सभी

Q.27) Solution (d)

भारतीय संदर्भ में छाया बैंकिंग

'छाया बैंकिंग प्रणाली' शब्द का पहली बार उपयोग 2007 में किया गया था तथा यह नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर संस्थाओं द्वारा किए गए बैंक जैसे कार्यों को संदर्भित करता है।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB), यानी, 'क्रेडिट मध्यस्थता जिसमें संस्थाओं और गतिविधियों (पूरी तरह या आंशिक रूप से नियमित बैंकिंग प्रणाली से बाहर)' शामिल हैं, द्वारा अपनाया गया है और अधिक व्यापक परिभाषा, विश्व स्तर पर स्वीकार की गई है। इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण घटक हैं:

बैंकिंग प्रणाली के बाहर गैर-बैंक वित्तीय संस्थाएँ या संस्थान जो परिपक्वता परिवर्तन की गतिविधियों जैसे 'बैंक' में संलग्न हैं, क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय उत्तोलन (financial leverage) का उपयोग करती हैं।

गैर-बैंक संस्थाओं के लिए धन के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में कार्य करने वाले प्रतिभूतिकरण, प्रतिभूतियों को उधार देने और रेपो लेनदेन जैसी गतिविधियाँ होती हैं। इस प्रकार, छाया बैंकों में ऐसी संस्थाएँ शामिल होती हैं जो सीधे वित्तीय मध्यस्थता का संचालन करती हैं, जैसे कि वित्त कंपनियाँ या एनबीएफसी, तथा ऐसी संस्थाएँ जो ऐसी संस्थाओं को म्यूचुअल फंड जैसे वित्त प्रदान करती हैं। वैश्विक स्तर पर, छाया बैंकिंग संस्थाओं को व्यापक प्रमुखों के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है

- मुद्रा बाजार फंड (Money Market Funds) ,
- क्रेडिट निवेश कोष
- हेज फंड
- वित्त कंपनियों का फंडिंग की तरह जमा स्वीकार करना
- क्रेडिट बीमाकर्ता, वित्तीय गारंटी प्रदाता
- प्रतिभूतिकरण वाहन (Securitisation vehicles)

छाया बैंकिंग संस्थान निवेशकों और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और प्रणाली में तरलता उत्पन्न करते हैं। हालांकि ये संस्थाएँ बैंकों द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक मांग जमा को स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन वे व्यावसायिक बैंकों के समान सेवाएँ प्रदान करती हैं। तथा यह एक कारण था कि वे विदेश में विनियमन से बच गए हैं। छाया बैंकिंग प्रणाली 2008 में वित्तीय संकट से पहले अमेरिका में ऋण की पेशकश में नियमित बैंकिंग प्रणाली से आगे निकल गई थी।

Q.28) 'क्षेत्रक कोष' (Sector Funds) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. क्षेत्रक कोष, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं
2. क्षेत्रक कोष, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक जोखिम रखते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.28) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
क्षेत्रक कोष (Sector funds) वे म्यूचुअल फंड होते हैं जो पूरी तरह से उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जो किसी विशेष उद्योग या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम	चूंकि वे क्लोज-एंडेड फंड (closed ended funds) होते हैं, इसलिए उनके पास विविधीकरण का अभाव होता है, तथा वे विविध इक्विटी म्यूचुअल फंडों की तुलना

करते हैं। पहला कथन गलत है क्योंकि सेक्टर फंड्स क्लोज-एंड फंड होते हैं

में अधिक जोखिम भरे होते हैं।

Q.29) भारत में पार्टिसिपेटरी नोट्स (Participatory Notes) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को RBI द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी किए जाते हैं।
2. पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.29) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पार्टिसिपेटरी नोट जारी किए जाते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स बड़े हेज फंड को उनकी पहचान बताए बिना उनके संचालन को पूरा करने में सक्षम बनाता है।	पी-नोट्स ने हाल ही में इस मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी निधियों के विशाल प्रवाह के कारण महत्वपूर्ण बाजार का ध्यान आकर्षित किया है। पार्टिसिपेटरी नोट्स में निवेश करने वाली किसी भी इकाई को सेबी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह पंजीकृत एफआईआई से खरीदी गई होती है

Q.30) भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले मुख्य विधान निम्नलिखित में से कौन से हैं?

1. सेबी अधिनियम, 1992
2. कंपनी अधिनियम, 1956
3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956
4. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (Depositories Act)

सही कूट चुनें

- a) केवल 1, 2 और 3
- b) केवल 2, 3 और 4
- c) केवल 1, 3 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.30) Solution (d)

प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले चार मुख्य विधान हैं:

- सेबी अधिनियम, 1992 जो निवेशकों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए सेबी की स्थापना करता है;
- कंपनी अधिनियम, 1956, जो प्रतिभूतियों के निर्गमन, आवंटन और हस्तांतरण, तथा सार्वजनिक प्रस्तावों (public issues) में किए जाने वाले निर्गमन के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, जो स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रतिभूतियों में लेनदेन के नियमन का प्रावधान करता है; तथा
- डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 जो इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव और डीमैट सिक्क्योरिटीज के स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करता है।

Q.31) मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शामिल है?

- a) भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL)
- b) सेबी
- c) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
- d) भारतीय रिजर्व बैंक

Q.31) Solution (a)

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Ltd- CCIL) की स्थापना अप्रैल, 2001 में मुद्रा, सरकारी-प्रतिभूति, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव्स बाजारों में लेनदेन के लिए गारंटीकृत समाशोधन और निपटान कार्य को प्रदान करने के लिए की गई थी। गारंटीकृत समाशोधन और निपटान की शुरुआत से बाजार में दक्षता, पारदर्शिता, तरलता और जोखिम प्रबंधन / माप पद्धतियों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ तथा साथ ही साथ, कम निपटान और परिचालन जोखिम, निपटान लागत पर बचत, आदि जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं।

CCIL रूपए लाभ दर डेरिवेटिव के लिए गैर-गारंटीकृत निपटान भी प्रदान करता है तथा CLS बैंक के माध्यम से क्रॉस-मुद्रा लेनदेन को संभव करता है। CCIL के वित्तीय बाजार अवसंरचना के रूप में अपने कार्यों को संचालित करने वाले कड़े सिद्धांतों का पालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2014 में एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) के रूप में अपनी मान्यता के परिणामस्वरूप किया गया है। इसने वित्तीय संस्थानों को OTC डेरिवेटिव में उनके लेनदेन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए एक ट्रेड रिपोजिटरी भी स्थापित की है।

CCIL वित्तीय बाजार में विभिन्न भूमिकाओं को लेने के लिए वित्तीय क्षेत्र के स्थानांतरण प्रतिमानों के साथ वर्ष दर वर्ष विकसित हुआ है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम्स लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से, सीसीआईएल ने विभिन्न बाजार खंडों में समझौतों के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पेश किए हैं। इसके अलावा, सीडीएसएल ने एनडीएस-ओएम को विकसित, कार्यान्वित और प्रबंधित किया है - आरबीआई के पास सरकारी-प्रतिभूतियों में निपटने के लिए बेनामी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है और ओटीसी समझौतों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ एनडीएस-कॉल मंच भी है जो कॉल में इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार की सुविधा देता है।

Q.32) विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal) निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है?

- a) वित्त मंत्रालय
- b) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

- c) विदेश मंत्रालय
- d) कारपोरेट कार्य मंत्रालय

Q.32) Solution (b)

भारत में कोई भी निवेश - या तो स्वचालित रूट के तहत जिसे आरबीआई से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है या सरकारी रूट के तहत, जिसे संबंधित मंत्रालयों / विभागों से एक खिड़की के माध्यम से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है - उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन के लिए विभाग (DPIIT) द्वारा प्रशासित विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफबी) से कर सकता है।

विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (Foreign Investment Facilitation Portal)

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया ताकि FDI अंतर्वाह को गति दी जा सके तथा देश में FDI अनुमोदन में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। FIFP ने मई, 2017 में FIPB का स्थान लिया।
- विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (FIFP) निवेशकों के लिए भारत सरकार का नया ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा देता है। यह पोर्टल उद्योग और आंतरिक व्यापार के संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।
- यह पोर्टल उन अनुप्रयोगों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा जारी रखेगा जो अनुमोदन मार्ग से होते हैं। एफडीआई आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया करेगा।

Q.33) अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

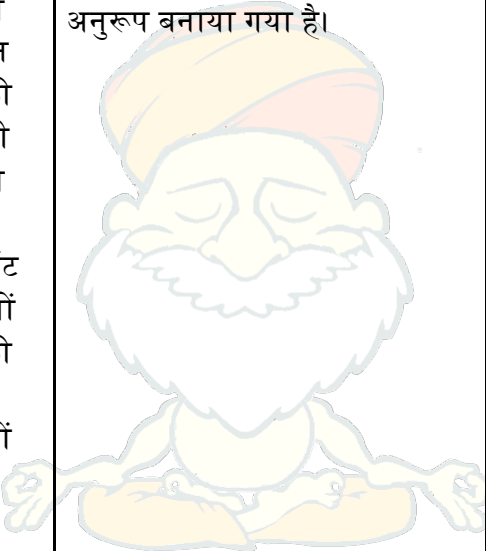
1. वे संस्थानों की तरह म्यूचुअल फंड हैं जो व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से पैसे की छोटी रकम जमा करके बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को सक्षम बनाते हैं
2. वे रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA)) द्वारा विनियमित होते हैं
3. InvITs केवल विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 1 और 2

Q.33) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं हैं, जो अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निवेश करने में सक्षम	भारत में प्रतिभूतियों के बाजार नियामक- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा InvITs का विनियमन किया जाता	InvITs बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, या तो सीधे या एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी)

बनाती हैं, ताकि बुनियादी ढांचा में सीधे निवेश के लिए व्यक्तिगत निवेशकों की भीड़ से छोटी रकम जुटाई जा सके, ताकि यूनिट के आय का एक हिस्सा (व्यय में कटौती के बाद), InvITs के धारक, जो पैसे में जमा हुए हैं, उन्हें लाभ का अंश वापस किया जा सके। InvITs के प्रकार दो प्रकार के InvITs को अनुमति दी गई है, एक जो मुख्य रूप से पूर्ण और राजस्व सृजन करने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति है तथा दूसरी जिसमें पूर्ण / निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करने की सुविधा है। जबकि पूर्व को अपनी इकाइयों की सार्वजनिक पेशकश करनी होती है, बाद वाले को अपनी इकाइयों के निजी प्लेसमेंट का विकल्प चुनना होता है। दोनों संरचनाओं को सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। चुनिंदा राज्य संचालित कंपनियों के विमुद्रीकरण के लिए अवसंरचनात्मक निवेश ट्रस्ट्स (InvITs) की घोषणा बजट 2018-19 में की गई थी।	है। SEBI ने SEBI (Infrastructure Investment Trusts) विनियम, 2014 को 26 सितंबर 2014 को अधिसूचित किया, जो भारत में InvITs के पंजीकरण और विनियमन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। InvIT का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की सुविधा प्रदान करना है। संरचना और परिचालनों में InvITs रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) से बहुत मिलते-जुलते हैं। InvITs संशोधित REITs हैं जिन्हें भारत में विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया है। 	के माध्यम से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, ऐसे निवेश केवल एसपीवी के माध्यम से हो सकते हैं।
--	--	---

Q.34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भुगतान संतुलन देश के नागरिकों और संसार के बाकी हिस्सों के बीच लेनदेन की गणना करता है।
2. पूंजीगत खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
3. किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है।

उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 2

Q.34) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
भुगतान संतुलन (बीओपी) एक देश के निवासियों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेनदेन को निर्दिष्ट समय अवधि के लिए संसार के बाकी हिस्सों के साथ होता है, जिसे आम तौर पर एक वर्ष में रिकॉर्ड किया जाता है। भुगतान संतुलन (बीओपी), जिसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन के रूप में भी जाना जाता है, सभी लेनदेन को संक्षेप में बताता है कि देश के व्यक्ति, कंपनियां और सरकारी निकाय देश के बाहर व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों के साथ लेनदेन को सारांशित करते हैं। इन लेनदेन में माल, सेवाओं और पूंजी के आयात और निर्यात के साथ-साथ विदेशी सहायता और प्रेषण जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल होते हैं।	भुगतान संतुलन एक पूंजी खाते और एक चालू खाते से बना होता है - हालांकि एक संकीर्ण परिभाषा पूंजी खाते को एक वित्तीय खाते और एक पूंजी खाते में तोड़ देती है। लेखांकन में, पूंजी खाता एक विशिष्ट समय में एक व्यापार के निवल मूल्य को दर्शाता है - और अन्यथा शेयरधारकों की इक्विटी के रूप में जाना जाता है। भुगतान संतुलन में परिवर्तन से देश के आर्थिक स्वास्थ्य के सापेक्ष स्तर और भविष्य की स्थिरता के बारे में कई साक्ष्य मिल सकते हैं। पूंजी खाता इंगित करता है कि कोई देश पूंजी का आयात या निर्यात कर रहा है या नहीं। पूंजी खाते में बड़े बदलाव यह संकेत दे सकते हैं कि विदेशी निवेशकों के लिए एक देश कितना आकर्षक है और विनिमय दरों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।	क्योंकि सभी लेन-देन शून्य से भुगतान राशि में दर्ज किए गए हैं, जो देश बड़े व्यापार घाटे (चालू खाता घाटे) में रहते हैं, परिभाषा के अनुसार बड़े पूंजी खाता अधिशेष भी रहने चाहिए - जिसका अर्थ है कि किसी देश के अधिशेष पूंजीगत खाते के ज़रिए उसकी परिसंपत्तियों के बढ़ते विदेशी स्वामित्व का संकेत मिलता है। एक बड़े व्यापार अधिशेष वाला देश पूंजी निर्यात कर रहा है, और पूंजी खाता घाटा हो रहा है - जिसका अर्थ है मुद्रा, देश से बाहर जा रही है।



Dedicated **HOTLINE (Communication channel) for all UPSC/IAS Aspirants**

Speak With the Founders and Core Team of Iasbaba on Telephone Regarding 'Any Queries' Related to UPSC Preparation in General or Subject-Specific Doubts.

2 HOURS DAILY (EXCEPT ON SUNDAYS) FROM 5PM TO 7 PM

- UPSC PREPARATION STRATEGY & CURRENT AFFAIRS – **9986190082**
- ENVIRONMENT & SCIENCE AND TECHNOLOGY – **9986193016**
- GEOGRAPHY & HISTORY – **9591106864**
- POLITY & ECONOMICS – **9899291288**

'ASK YOUR BABA' - Special feature to clear your doubts on the 60 Day Platform (Online from 10am - 10 pm)

WWW.IASBABA.COM

Q.35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अपना अब तक का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है

2. भारत में पिछले 5 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगातार बढ़ा है

उपरोक्त कथनों में से कौन

सा सही है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.35) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
एफडीआई आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है तथा देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वित्त का एक स्रोत है। सरकार ने एफडीआई पर एक निवेशक-अनुकूल नीति रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों / गतिविधियों में स्वचालित मार्ग पर 100 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति है।	एक स्थिर और अनुमानित विनियामक शासन, एक बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत बुनियादी बातों के कारण, भारत पिछले पांच वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बड़ी मात्रा को आकर्षित कर सका है, जोकि एफडीआई के रूप में प्राप्त 239 बिलियन अमरीकी डालर है। इस अवधि में एफडीआई नीति

उन्होंने कहा कि इन सुधारों के कारण भारत में 2014-15 से 2018-19 तक पाँच वर्षों में कुल एफडीआई बढ़कर 286 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि पिछले पांच वर्षों में 189 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। USD 64.37 बिलियन, 2018-19 में FDI किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक निवेश है।

का तेजी से उदारीकरण भी देखा गया, जिससे अधिकांश एफडीआई स्वतः मार्ग से आने लगे। लेकिन एफडीआई लगातार नहीं बढ़ा है।

Q.36) शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) किसी निश्चित समय में किसी देश के अदृश्य निर्यात और आयात मूल्य के बीच का अंतर है। इस संदर्भ में, गैर-कारक आय का गठन कौन करता है

1. श्रम पर अंतर्राष्ट्रीय आय
2. पूंजी पर अंतर्राष्ट्रीय आय
3. शिपिंग
4. बैंकिंग
5. पर्यटन

सही कूट चुनें

- a) केवल 1, 2, 3 और 4
- b) केवल 2, 3, 4 और 5
- c) केवल 3, 4 और 5
- d) उपरोक्त सभी



Q.36) Solution (c)

शुद्ध अदृश्य (Net Invisibles) एक निश्चित समय में किसी देश के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। अदृश्य योग्य में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, स्थानांतरण और प्रवाह की आय शामिल होती हैं। सेवा व्यापार में कारक और गैर-कारक आय दोनों शामिल हैं। कारक आय में उत्पादन के कारकों (जैसे श्रम, भूमि और पूंजी) पर शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय आय शामिल है। गैर-कारक आय शिपिंग, बैंकिंग, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाओं आदि जैसे सेवा उत्पादों की शुद्ध बिक्री है।

Q.37) 'अर्थव्यवस्था के खुलेपन' (openness of an economy) के स्तर को, निम्न में से किस कारक द्वारा मापा जाता है?

- a) विश्व जीडीपी में निर्यात और आयात का हिस्सा
- b) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात
- c) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भुगतान संतुलन
- d) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार संतुलन

Q.37) Solution (b)

खुलेपन को किसी देश के माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के रूप में मापा जाता है, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में होती है। तो, विकल्प b सही है

व्यापार संतुलन का अर्थ है निर्यात - आयात है, इसलिए विवरण d गलत है।

Q.38) क्रय शक्ति समता (PPP) विनिमय दरों के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि दो देशों में मुद्रास्फीति की दर शून्य है, तो उनकी पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी
2. पीपीपी विनिमय दर पर परिवर्तित होने पर दोनों देशों में सामान की कीमतें समान होंगी

उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है / हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) इनमें से कोई भी नहीं

Q.38) Solution (d)

मान लीजिए नॉमिनल विनिमय दर \$ 1 = 70 है तथा भारत और अमेरिका सिर्फ पिज्जा का उत्पादन करते हैं

	भारत	यू.एस.
पिज्जा की कीमत	35	\$ 1

पीपीपी विनिमय दर की गणना करने के लिए, हमें अमेरिका के साथ भारत में सामान की एक टोकरी की कीमतों की तुलना करने की आवश्यकता है।

भारत और अमेरिका में पिज्जा की कीमतों की तुलना करके उपरोक्त मामले में, हमें \$ 1 = 35 रु मिलता है तो, \$ 1 = 35 पीपीपी विनिमय दर है। इसका तात्पर्य है कि भारत में जो भी 35 रुपये खरीद सकता है, यूएस में \$ 1 खरीद सकता है यानी भारत में 35 रुपये की क्रय शक्ति यूएस में \$ 1 की क्रय शक्ति के बराबर है।

इसलिए, अगर देशों में मुद्रास्फीति की दर अलग है, तो पीपीपी विनिमय दर बदल जाएगी। लेकिन अगर कोई मुद्रास्फीति नहीं है (कीमतें समान हैं) तो पीपीपी विनिमय दरें स्थिर रहेंगी।

तो, कथन 1 सही है।

जब हम US में पिज्जा की कीमत को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए PPP एक्सचेंज (\$ 1 = 35 रु) की दर का उपयोग करते हैं तो यह 1 US में 35 रु. होता है जो भारत में भी वैसा ही है।

तो, कथन 2 भी सही है।

Q.39) भारतीय संदर्भ में, रुपये के मूल्यहास (depreciation) का क्या अर्थ है?

- a) विनिमय दर में वृद्धि जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
- b) विनिमय दर में वृद्धि जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
- c) विनिमय दर में कमी जहां विदेशी मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में भारतीय मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है
- d) विनिमय दर में कमी जहां घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में कमी आई है

Q.39) Solution (a)

विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है कि घरेलू मुद्रा (रुपये) के संदर्भ में विदेशी मुद्रा (डॉलर) की कीमत में वृद्धि हुई है। इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का मूल्यहास (Depreciation) कहा जाता है।

इसी तरह, एक लचीली विनिमय दर शासन में, जब विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) की कीमत बढ़ती है, तो इसे विदेशी मुद्रा (डॉलर) के संदर्भ में घरेलू मुद्रा (रुपये) का अभिमूल्यन (Appreciation) कहा जाता है।

Q.40) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. भारत 22 (Bharat 22), एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है जिसमें केवल 22 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (PSU) स्टॉक शामिल हैं
2. ईटीएफ में निवेश कम तरल होते हैं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जा सकता है
3. भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के प्रबंधन के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है

उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 2 और 3
- c) केवल 1 और 3
- d) केवल 3

Q.40) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
ETF एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका उद्देश्य अपने अंतर्निहित सूचकांक के प्रदर्शन को ट्रैक और प्रतिबिंबित करना है। यह उसी स्टॉक में निवेश करने की निष्क्रिय निवेश रणनीति के माध्यम से प्राप्त करता है और उसी अनुपात में जैसा कि वे अंतर्निहित सूचकांक का गठन करते हैं। सूचकांक में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी कंपनियों के 22 स्टॉक शामिल हैं, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रणनीतिक होल्डिंग (SUUTI) हैं। उक्त 22 स्टॉक छह क्षेत्रों (मूल सामग्री, ऊर्जा, वित्त,	ईटीएफ में निवेश अत्यधिक तरल है क्योंकि वे डीमैट खाते के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं तथा प्रत्यक्ष इक्विटी शेयरों जैसे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है। साथ ही, निष्क्रिय रूप से प्रबंधित होने के कारण, उनके पास सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंडों की तुलना में कम व्यय वाले अनुपात होते हैं। भारत 22 ईटीएफ सरकार को एक ईटीएफ में चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी होल्डिंग संग्रहित करने और एक बार में निवेशकों से विनिवेशित धन जुटाने की अनुमति देता है। यह विशेष रूप से निर्मित S & P BSE Bharat 22 सूचकांक, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ को बनाने, लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को नियुक्त किया है।

एफएमसीजी, उद्योग और Utilities) में फैले हैं। सूचकांक एकल स्टॉक में अधिकतम 15 प्रतिशत और किसी विशेष क्षेत्र में 20 प्रतिशत निवेश करता है। भारांश प्रतिवर्ष पुनर्संरचित किया जाता है।	द्वारा प्रबंधित करता है। यह सूचकांक 22 पीएसयू शेयरों और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों से बना है।	
---	---	--

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.

